साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 06-12 नवंबर 2023 वर्ष-9, अंक-30

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्यः- 2 रुपए

अव्यवस्थाओं के बीच मंडी में की जा रही धान की नीलामी

-सीजन में पहली बार 600 ट्रॉलियों में आई 15 हजार क्विंटल

धान और मक्का से कृषि उपज मंडी 'धन्य'

रायसेन। जागत गांव हमार

रायसेन कृषि उपज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। जैसे ही मंडी खुली उसके साथ ही 600 ट्राली धान से लदी हुई मंडी में पहुंची। इसमें 15000 क्विंटल धान थी। ट्रालियों की लाइन दशहरा मैदान में लगी हुई थी। धान की इतनी बड़ी पैमाने पर आवक होने से देर रात तक तुलाई का काम चलता रहा। रायसेन मंडी में व्यापारियों ने किसानों को 3200 रुपए से लेकर 4100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धन बेची है। किसानों को इस बार धान की फसल की अच्छी कीमत मंडी में मिली है।

किसानों को परेशानी

रायसेन मंडी में धान की उपज लेकर पहुंच रहे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन द्वारा किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसानों को अपनी धान की नीलामी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

गुना मंडी में मक्के की बंपर आवक

कृषि उपज मंडी गुना में 50000 क्विंटल अनाज की आवक हुई है। इसमें 40000 टन मक्के की आवक हुई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लग गई थी। कई किलोमीटर तक यह लाइन लगी रही। दशहरा की छुट्टियों के बाद पहली बार मंडियों में बड़ी आवक अनाज की देखने को मिल रही है।

13 करोड़ रुपए का गेहूं बर्बाद होने का अनुमान

» भंडारण में खामी गोदाम में रखा गेहूं खराब

» आंकड़े में और भी इजाफा होने की संभावना

राशन दुकानों में पहुंचा 20 हजार क्विंटल घटिया गेहूं

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश की कई राशन दुकानों पर इतने घटिया स्तर का गेहूं-चावल भेजा गया कि उसे इंसान तो क्या जानवर भी न खाएं। खासतौर पर गुना जिले के चांचौड़ा-कुंभराज क्षेत्र की कई दुकानों पर इसका वितरण हो गया। जबकि इस पर रोक लगा दी गई थी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीनागंज स्थित वेयर हाउस से दुकानों पर यह गेहूं-चावल कैसे भेज दिया गया, इसकी जांच की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिले की राशन दुकानों के लिए जबलपुर से करीब 20 हजार क्विंटल चावल-गेहूं की रैक भेजी गई थी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा माल ही खराब है। हमने इसकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। साथ ही वेयरहाउस से इस अनाज को राशन दुकान न भेजने के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह का अनाज ग्वालियर की भी कुछ राशन दुकानों में भेजा गया है।

जनवरी में होगा अनाज संकट

फिलहाल राशन दुकानों के लिए गुना में गेहूं-चावल का इतना स्टॉक है कि दिसंबर तक का काम चल जाएगा। इस बीच अगर नई रैक नहीं आई या फिर जबलपुर से आए माल का फैसला न हुआ तो, जनवरी में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा।

लाखों रुपए परिवहन पर खर्च

इस घटिया गेहूं-चावल को जबलपुर के विभिन्न हाउस से वेयर हाउस से वहां के रेलवे स्टेशन तक पहुंचा गया। इसके बाद रेलवे की पूरी रैक बुक कराकर गुना तक यह आया। यहां से इसे ट्रकों के जरिए अन्य स्थानों पर भेजा। इस पर लाखों रुपए परिवहन में ही खर्च कर दिए गए। धान और मूंग के रखरखाव में गड़बड़ी की शिकायत के बाद अब गेहूं के भंडारण में खामी देखने को मिली है। इस खामी के चलते करीब 13 करोड़ का गेहूं बर्बाद होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

जबलपुर से करीब 20 हजार क्विंटल अनाज आया था। जांच में उसकी क्वालिटी बहुत खराब पाई गई। हमने चारों वेयर हाउस के प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे इस राशन दुकानों पर न भेजें।

टी कुर्रे, जिला आपूर्ति अधिकारी

जिले में अनेक वेयर हाउसों में रखा करीब 55 हजार क्विंटल गेहूं खराब हो चुका है। इसकी कीमत करीब 13 करोड़ है। वेयर हाउसों की जांच जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा की जा रही हैं। जल्द रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

-दिलीप किरार, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम

बैंगन की पैदावार में सबसे आगे बंगाल

बैंगन की पैदावार में 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश

भोपाल। बैंगन का भरता हो, सब्जी हो या पकौड़ा... खाने में यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पर क्या आप जानते हैं कि बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी कहां से पूरे देश में सबसे अधिक पहुंचता है बैंगन। इसके लिए पढ़ें **जागत गांव हमार** की ये रिपोर्ट...। भारत में सबसे अधिक बैंगन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यानी बैंगन उत्पादन के मामले में ये राज्य अव्वल है। यहां के किसान हर साल बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। देश के कुल बैंगन उत्पादन में बंगाल की 23.72 फीसदी की हिस्सेदारी है। यहां की मिट्टी और जलवायु बैंगन की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। बैंगन की मांग बाजार में हमेशा ही रहती है। आज कल बैंगन के भर्ते की मांग घर से लेकर फाइव स्टार होटलों तक भी रहती है। वहीं उत्पादन की बात करें तो इसमें ओडिशा का भी नाम है जहां के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं।

बैंगन बारहमासी पौधा

देश के कुल बैंगन उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 16.66 फीसदी है। बैंगन लम्बे समय तक उपज देता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बैंगन एक बारहमासी पौधा है। वहीं उत्पादन के मामले में भारत के टॉप तीन राज्यों में तीसरा नंबर गुजरात का है। यहां बैंगन का 12.01 फीसदी उत्पादन होता है। बैंगन में भरपूर मात्रा में पोषक भी होते हैं। इसमें कम कैलोरी में विटामिन, आयरन और फाइबर पाई जाती है।

बिहार चौथे नंबर पर

बिहार बैंगन के उत्पादन में चौथे नंबर पर है। यहां हर साल 9.43 फीसदी बैंगन का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के (वर्ष 2021-22) आंकड़ों के अनुसार बैंगन की पैदावार में पांचवें स्थान पर मध्य प्रदेश है। यहां हर साल किसान 8.74 फीसदी बैंगन का उत्पादन करते हैं। वहीं ये पांच राज्य मिलकर 70 फीसदी बैंगन का उत्पादन करते हैं।

कड़कनाथ बेचने वालों के साथ-साथ अंचल के ढाबों वालों की भी चांदी

कड़कनाथ के बढ़े भाव! 750 का मुर्गा अब 2000 रुपए का

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल है। धीरे-धीरे चुनाव प्रचार अभियान में तेजी देखी जा रही है। साथ ही साथ उतनी ही तेजी मप्र के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे के दामों में भी देखी जा रही है। झाबुआ का विश्व प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा आम दिनों में 750 रुपए प्रतिनग बिकता था। वही इन दिनों 1500 से 2000 रुपए के बीच त्वरित उपलब्धता की शर्तों पर बिक रहा है। इससे कड़कनाथ बेचने वालों के साथ-साथ अंचल के ढाबों वालों की भी चांदी हो गई है। आखिर कड़कनाथ मुर्गे के दामों में अचानक उछाल क्यों आया है। इस सवाल के जवाब में कड़कनाथ विक्रेताओं ने बताया कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, उस समय ठंड का मौसम होता है। उस पर से बड़ी तादाद में बाहरी प्रदेशों और जिलों से प्रचार करने या प्रचार देखने ऐसे लोग आते हैं, जो झाबुआ आने पर कड़कनाथ खाने की इच्छा रखते हैं। अपने स्थानीय संपर्कों की मदद से वह अपना शौक पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे मांग बढ़ती है और पूर्ति प्रभावित होती है, इसलिए दाम लगभग दोगुने हो जाते हैं। जिले के चिकन विक्रेता यामीन कहते हैं कि वह तो हर पांचवें साल यानी विधानसभा चुनाव के वर्ष में वोटिंग के चार-पांच महीने पहले से चूजे लेकर बड़ा करते हैं और प्रचार अभियान के दौरान अच्छा मुनाफा कमाते हैं।

चुनावी साल में कड़कनाथ मुर्गे महंगे हो जाते हैं, लेकिन यह अच्छा है। कम से कम कड़कनाथ का धंधा करने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को तो मुनाफा हो रहा है। उनका रोजगार तेजी से चल रहा है। आदिवासी आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

कमलेश, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष

कड़कनाथ झाबुआ की पहचान है और इस पहचान से चुनावी मौसम में स्थानीय कड़कनाथ विक्रेताओं को मुनाफा हो रहा है तो अच्छी बात है। कड़कनाथ मुर्गा मूलतः मध्यप्रदेश के झाबुआ का ब्रीड है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे झाबुआ का कड़कनाथ नाम से जीआई टैग दिया हुआ है।

दौलत भावसार, भाजपा नेता, झाबुआ

कड़कनाथ का रंग इसलिए काला होता है कि इसमें अतिरिक्त आयरन और मेलोनिन पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गे के सेवन से मानव शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए इसके सेवन की सलाह दी जाती है।

डॉ. चंदन राय, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, झाबुआ

गेहूं का दाम कंट्रोल करने केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

रियायती दर पर गेहूं की बिक्री मार्च तक जारी रहेगी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने गेहूं के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम, डोमेस्टिक (ओएमएसएस-डी) के तहत बाजार के मुकाबले काफी रियायती दर पर गेहूं की बिक्री 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। तब तक इस योजना के तहत 101.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगले साल आने वाली गेहूं की नई फसल का दाम भी सरकार बढ़ने नहीं देना नहीं चाहती। हालांकि इस स्कीम से किसानों को पहले भी बड़ा नुकसान हुआ है और अगले साल भी होगा। क्योंकि जब सरकार खुद बाजार रेट से काफी सस्ते दर पर गेहूं बेचेगी तो फिर किसानों को कौन अच्छा दाम देगा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि व्यापारियों को ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए पहले से लगी गेहूं की 3000 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट को घटाकर अब 2000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसकी बारीकी से निगरानी हो रही है। स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए 31 अक्टूबर तक देश भर में 1721 औचक जांच की गई है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई बनावटी कमी पैदा न हो। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण की मंशा से ही 13 मई 2022 से गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाई हुई है।

सस्ता गेहूं बेचती है सरकार

केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के जरिए ओएमएसएस के तहत आम उपभोक्ताओं को सस्ता गेहूं नहीं बेचती है। सस्ता गेहूं मिलता है बड़े मिलर्स और कुछ सरकारी एजेंसियों को। इस साल गेहूं का दाम जब बढ़ने लगा तो सरकार ने 25 जनवरी को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत रियायती रेट पर गेहूं बेचने का एलान किया गया था। एक फरवरी से 15 मार्च तक 33 लाख टन गेहूं बेचा गया। उसके बाद केंद्रीय पूल भंडार से 12 जून को 15 लाख टन गेहूं की बिक्री करने का एलान किया गया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने फिर 9 अगस्त को 50 लाख टन गेहूं बेचने का एलान किया।

कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश

मंत्रालय के अनुसार एक नवंबर को ओएमएसएस के तहत वर्ष 2023-24 की 19वीं ई-नीलामी आयोजित की गई। एक नवंबर को हुई ई-नीलामी में 2389 बोलीदाताओं को 2.87 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप करने की भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित की जा रही है। खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, गेहूं की साप्ताहिक पेशकश की मात्रा को बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक तक अधिकतम किया गया है।

मिलर्स को सस्ता दिया जा रहा गेहूं

एफएक्यू गेहूं के लिए औसत बिक्री मूल्य 2291.15 रुपए प्रति क्विंटल था। जबकि आरक्षित मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल था। एफएक्यू गेहूं का मतलब, जो सभी विशिष्टताओं को पूरा करता है। इसमें चमक होती है। दूसरी ओर यूआरएस गेहूं का औसत बिक्री मूल्य 2311.62 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि इसका आरक्षित मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल था। हालांकि उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार 2 नवंबर को देश में गेहूं का औसत दाम 30.58, अधिकतम भाव 58 रुपए और मॉडल प्राइस 28 रुपए प्रति किलो था।

आलू-बैगन छोड़कर सभी हुई महंगी

सब्जी की आवक कम होने से दाम बढ़े, प्याज ने फिर निकाले आंसू

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी भोपाल में शहरी और नगरीय क्षेत्र में सब्जी की आवक कम हो गई है। जिससे प्याज, टमाटर, भिंडी, बरबटी और शिमला मिर्च की कीमतों में 40 से 80 रुपए तक का उछाल आ गया है। वहीं धनिया पत्ती खुले बाजार में 200 रुपए किलो पहुंच गई है। साथ ही इस सीजन में आने वाली सब्जियां 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही हैं। जिससे त्योहारी सीजन खर्च के साथ ही आम लोगों पर सब्जी खरीदी का बोझ बढ़ गया है। वहीं सब्जी विक्रेता आगामी दिनों में और अधिक भाव बढ़ने की बात कह रहे हैं। आगामी धनतेरस और दीपावली पर्व पर आम लोगों को अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। वहीं अचानक सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी को अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। पिछले सप्ताह तक 30 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 80 रुपए, 40 रुपए वाली भिंडी 70 रुपए, 40 रुपए वाली बरबटी 80 रुपए और 100 रुपए किलो बिकने वाली धनिया पत्ती 200 रुपए पहुंच गई है। वहीं सर्दी के सीजन में आने वाली मैथी और चना की भाजी 160 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी व्यापारी बताते हैं कि इनदिनों बी सीजन की बोवनी चल रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली सब्जी कम मात्रा में आ रही है। इसलिए थोक बाजार में सब्जी की आवक कम हो गई है। इसलिए आलू और बैंगन छोड सभी की कीमत बढ़ गई है।

त्योहार के बीच बढ़ा खर्च

त्योहारों के बीच आम आदमी का बिगड़ा बजट शहर की ग्रहणी पूनम जगधारी, सपना चौहान ने बताया कि सब्जी के दाम बढ़ने से परिवार का बजट गड़बड़ा गया है। क्योंकि इस माह दशहरा पर्व रहा और अगले माह दीपावली पर्व आने वाला है, जिसमें लोगों को अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। पिछले सप्ताह तक जो सब्जी 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वह आज 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। इस में आने वाली सब्जियां 150 रुपए के ऊपर बिक रही हैं।

चमड़े के सामान बनाने में भी होगा इस्तेमाल

अब नारियल की मलाई से बनेंगे कपड़े

भोपाल। जागत गांव हमार

आज कल बनाना फाइबर शब्द बहुत मशहूर है। बनाना फाइबर का अर्थ है केले के तने से बना फाइबर। चौंकाने वाली बात ये है कि अब इस तने से निकले फाइबर से कई तरह के फैशन प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि इसके रेशे से कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के एक रिसर्चर ने नारियल की मलाई से ऐसा फाइबर बनाया है जो जानवरों के चमड़े की जगह ले सकता है और उससे कई तरह के फैशनेबल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इस नई रिसर्च में नारियल के पानी को फर्मेंट कर एक नए तरह का मटीरियल बनाया गया है जो फाइबर का काम करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मलाई से फाइबर बनाने का काम केरल की फैशन डिजाइनर जुजाना गोंबोसोवा ने किया है। जुजाना पिछले पांच साल से केरल में रहती हैं और नारियल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करती हैं। इसके लिए उन्होंने अपना स्टार्टअप मलाई बायोमेटीरियल्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया है। उनका यह स्टार्टअप दक्षिण भारत के अलग-अलग स्थानों से बेकार नारियल पानी इकट्ठा करता है और उससे सेल्युलोज बनाया जाता है, फिर इसी सेल्युलोज से फाइबर बनता है।

नारियल पानी से बनी मलाई होते हैं कई रंग

जुजाना गोंबोसोवा कहती हैं कि हर दिन 4,000 लीटर नारियल पानी से 150-170 किलो सेल्युलोज बनाया जाता है, फिर इस सेल्युलोज को रिफाइन कर कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नारियल पानी से बनी मलाई कई अलग-अलग रंगों में होती है जिसे प्राकृतिक डाई से तैयार किया जाता है। यह मलाई शीट यानी कि चादर के रूप में तैयार की जाती है।

केरल की जलवायु मलाई फर्मेंट के लिए उपयुक्त

हालांकि इस मलाई को बनाने में नारियल पानी के अलावा केले के तने से निकले फाइबर, भांग और सिसल का भी प्रयोग होता है। जब मलाई तैयार होती है तो वह नरम, टिकाऊ और वाटर प्रूफ होती है। जुजाना कहती हैं कि उन्होंने मलाई बनाने का काम पहले कर्नाटक में शुरू किया था, लेकिन 2018 में केरल आ गईं क्योंकि वहां का मौसम, जलवायु और तापमान मलाई को फर्मेंट करने के लिए उपयुक्त हैं।

जानवरों के चमड़े की जगह मलाई से बनेगा प्रोडक्ट

जुजाना और उनके स्टार्टअप ने अब अधिक मात्रा में सेल्युलोज और फाइबर बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में उनकी प्लानिंग अब फैशन दुनिया में उतरने की है। जुजाना का स्टार्टअप हर महीने मलाई से लगभग 200 वर्ग मीटर कच्चा माल बना रहा है जिसकी कीमत 2,000 से 4,000 वर्ग मीटर के आसपास है। दुनिया में आजकल नेचुरल प्रोडक्ट की बहुत मांग है और लोग इसका इस्तेमाल भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जानवरों के चमड़े की जगह अगर मलाई से बना फाइबर प्रयोग किया जाए तो लोगों को और भी पसंद आएगा। कुछ यही सोचकर जुजाना ने अपने स्टार्टअप का काम बढ़ाया है।

गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली का सबने मिलकर उठाया जिम्मा

गांव वालों ने गोबर गैस को अपनाया, यह काम 5 परिवारों से प्रेरित होकर किया

सरकार और समाज ने मिलकर जुटाई चंबल के गांव में नागरिक सुविधाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में विकास के तमाम दावों को ग्रामीण स्तर पर 5 कसौटियों पर खरा उतरने की दरकार होती है। राष्ट्रीय विकास की प्राथमिक इकाई गांव होता है। इसलिए गांव के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सहूलियत मुहैया कराने को विकास की 5 कसौटी के रूप में चिन्हित किया गया है। आम तौर पर गांव या शहर में इन 5 मूलभूत सुविधाओं की बहाली नहीं हो पाने के लिए सरकारों को कोसा जाता है। खासकर दूरदराज के गांवों के बारे में ये माना जाता है कि इनमें 5 मौलिक सुविधाएं भी लोगों को मयस्सर नहीं हैं। मगर, देश के कुछ गांव ऐसे भी हैं, जो इस धारणा को गलत साबित कर रहे हैं। इनमें मप्र के सबसे ज्यादा पिछड़े चंबल संभाग का मैथाना गांव भी शामिल है। ग्वालियर जिले के एक गांव में सरकार और समाज के सहयोग से मूलभूत नागरिक सुविधाओं की बहाली का श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया गया है।

सामाजिक संगठनों ने निभाई जिम्मेदारी– ग्वालियर से महज 15 किमी दूर मैथाना गांव में समाज कार्य की बेहतर परंपरा आज भी जीवित रखा गया है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता रामसिंह किरार ने बताया कि गांव के कुछ सक्रिय युवा सफाई के इंतजाम करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इससे प्रभावित होकर सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली का जिम्मा उठाया।

दो डॉक्टर दे रहे नियमित सेवा

सरकार की तरफ से गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना था, लेकिन कुछ साल पहले मैथाना गांव ग्वालियर नगर निगम का हिस्सा बन गया। इस वजह से स्वास्थ्य केंद्र बनने का काम अधर में लटक गया। इसके विकल्प के रूप में गांव वालों ने मिलकर भारत विकास परिषद को गांव के स्कूल के अहाते में जगह देकर एक डिस्पेंसरी शुरू करने का रास्ता सुगम कर दिया। इसके बाद गांव में दो साल पहले एक डिस्पेंसरी बन गई। इसमें दो डाक्टरों की नियमित सेवा के साथ जरूरी दवाएं मुफ्त में दी जाने लगी हैं।

बंद होने से बच गया स्कूल

गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों का निर्धारित संख्या से कम दाखिला हो पाने के कारण स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। मगर गांव वालों की सक्रियता के कारण ऐसा नहीं हो सका। स्कूल के टीचर एक साथ तीन क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर हुए, इससे स्कूल बंद होने के बजाए नियमित रूप से चल रहा है। किरार ने कहा कि गांव के लोग यदि किसी समस्या के लिए सरकार को कोसने के बजाए थोड़ा सक्रिय होकर सामाजिक सहयोग करें, तो मूलभूत सुविधाएं अपने बलबूते भी गांव में बहाल कर सकते हैं।

ऊर्जा संरक्षण की नजीर गांव

मैथाना गांव में कुल 52 परिवार रहते हैं। इनमें से 34 परिवार गोबर गैस का इस्तेमाल करते हैं। उज्जवला योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से गैस के सिलेंडर देने के क्रम में मैथाना गांव के तमाम परिवारों को सिलेंडर नहीं मिल पाए। इससे सरकार को कोसने के बजाय गांव वालों ने विकल्प के रूप में गोबर गैस को अपना लिया। यह काम गांव के उन 5 परिवारों से प्रेरित होकर किया गया जो पिछले 25 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे।

पशु पालकों को दोहरा लाभ

गोबर गैस का सबसे पहले इस्तेमाल शुरू करने वाले रामबाबू ने बताया कि उनके घर में लगभग एक दर्जन गाय भैंस हैं। वह इनके गोबर से रसोई गैस प्राप्त कर इससे बची सलरी को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें दोहरा लाभ होता है। पहला तो गैस सिलेंडर का खर्च बचता है, साथ ही साफ ईंधन के इस्तेमाल से परिवार की सेहत और खाद से खेत की सेहत बेहतर रहती है। उनके इस फार्मूले को अब गांव के 34 परिवारों ने अपना लिया है। इससे उनका गांव ऊर्जा संरक्षण की नजीर बनकर उभरा है।

गांव में होती है नियमित सफाई

किरार ने बताया कि गांव के बुजुर्ग सफाई व्यवस्था पर पूरी नजर रखते हैं। गांव में पंचायत व्यवस्था खत्म होने के बाद नगर निगम का वार्ड बनने पर पार्षद को नियमित तौर पर सफाई कर्मी भेजना पड़ता है। इस पर पूरी निगरानी रखी जाती है। इसके परिणामस्वरूप गांव में नियमित रूप से सफाईकर्मी आते हैं और सड़क एवं नाली की सफाई भी होने से गांव की गलियों में गंदगी नहीं पनप पाती है। गांव के लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग करने के प्रति जागरुक कर गांव में जगह जगह दो तरह के कूड़ेदान रखे गए हैं। इनसे सूखा और गीला कचरा का उठान होता है।

मप्र से बिहार नौकरी करने गए युवक ने लगाई ड्रोन स्टार्टअप कंपनी

अब बिहार से मजदूर नहीं, तकनीक दूसरे राज्य में जाएगी

देश का पहला स्वदेशी तीस लीटर वाला ड्रोन लांच करने की तैयारी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले मनीष दीक्षित करीब 11 साल पहले बिहार के बच्चों को टेक्नोलॉजी का पाठ पढ़ाने के लिए पटना गए थे। लेकिन आज वो बिहार में कृषि ड्रोन बना रहे हैं। ये सूबे के पहले युवा उद्यमी हैं, जो अपना स्टार्टअप का काम ड्रोन के क्षेत्र में कर रहें हैं। अपने दो साल के सफर में वे कृषि के क्षेत्र में कई तरह के ड्रोन बना चुके हैं। अब वे भारत का पहला स्वदेशी तीस लीटर क्षमता वाला कृषि ड्रोन लांच करने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही टैक्सी ड्रोन बनाने के काम में लगे हुए हैं।

मनीष दीक्षित कहते हैं कि ऐसा पहली बार है, जब बिहार राज्य में बने ड्रोन की मांग देश सहित विदेशों में भी है। वहीं आने वाले समय में बिहार से सबसे अधिक ड्रोन पायलट तैयार करने की योजना है।आधुनिक खेती की कल्पना ड्रोन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि मजदूरों की कमी को देखते हुए ये ड्रोन खेती के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। वहीं अब बिहार से मजदूर नहीं बल्कि यहां से ड्रोन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी दूसरे राज्यों में जाएगी।

15 हजार की नौकरी करने गए थे बिहार– मनीष दीक्षित के अनुसार वे बिहार के पहले युवा उद्यमी हैं जिन्होंने 2022 में ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी स्थापित की है। उन्होंने बताया कि 2012 में ग्वालियर से पटना 15000 रुपए की सैलरी पर नौकरी करने आए थे, लेकिन 6 महीना नौकरी करने बाद एक विद्यार्थी के द्वारा बनाए गए कृषि ड्रोन से प्रभावित होकर इस क्षेत्र में कदम रखा। इन्होंने 2022 में वनामिका एयरोस्पेस नाम से ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी स्थापित की। पिछले आठ महीने के दौरान 32 करोड़ का ड्रोन ऑर्डर हुआ है। आज दोनों कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ तक हो गया है।

देश का पहला तीस लीटर वाला कृषि ड्रोन

मनीष दीक्षित देश का पहला कृषि ड्रोन आने वाले समय में लांच करने जा रहे हैं जिसकी क्षमता तीस लीटर होगी। इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अभी तक देश में दस लीटर तक का ही कृषि ड्रोन है, लेकिन इस ड्रोन की क्षमता तीस लीटर तक है। यह एक बार में तीन एकड़ तक दवा का छिड़काव कर सकता है। वहीं पूरे दिन में 80 एकड़ तक दवा का छिड़काव करेगा जो करीब 20 मजदूर 20 दिन में कर पाएंगे।

2020 के बाद बढ़ी ड्रोन की मांग

दीक्षित ने कहा कि भारत सरकार की सफल योजनाओं के जरिये करीब तीन साल के दौरान ड्रोन का बाजार 08 मिलियन तक पहुंच गया है। आज बिहार के बने ड्रोन की मांग देश सहित विदेशों में हो रही है। वहीं आने वाले समय में ड्रोन कृषि वैज्ञानिक के तौर पर काम करेगा। इसके साथ ही अब बिहार से मजदूर नहीं, तकनीक दूसरे राज्य में जाएगी।

किसानों को नहीं मिला रहा सोयाबीन का सही भाव

-मंडी में नहीं बढ़ पा रही सोयाबीन की आवक

उज्जैन। जागत गांव हमार

इस बार खरीफ के सीजन में पीले सोने की आवक नही बढ़ पा रही है। जबकि नए सोयाबीन की कटाई होकर खेतों में गेहूं की बोवनी शुरू हो गई है। ऐसे में मंडी प्रांगण में गत वर्ष की बनिस्बत कम रौनक है।

किसानों ने सोयाबीन के भाव कम मिलने से बिक्री से हाथ खींच रखा है। सोयाबीन का सीजन शुरू हुए करीब डेढ़ माह हो गया है, लेकिन आवक 12 से 15 हजार बोरी पर ही स्थिर है। जबकि दीपावली पर्व के चलते आवक में इजाफा हो जाना था। किसानों का कहना है कि बीज की सोयाबीन के भाव को छोड़ दें तो सामान्य क्वालिटी की सोयाबीन 4500 से 4800 रुपए क्विंटल बिक रही है। यह लागत से भी कम है। ऐसे में किसान आवश्यकता अनुसार ही पीले सोने की बिक्री कर रहा है। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार का तेल आयात का फैसला सोयाबीन की तेजी में बाधक बना हुआ है। ऐसे में प्लांट वालों ने खरीदी भाव कम कर रखे हैं। बीज वाला सोयाबीन 6300 रुपए क्विंटल बिकने लगा है। कृषि उपज मंडी में दीपावली अवकाश 8 दिन का घोषित किया गया है। नीलामी मुहूर्त 18 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 33 मिनट पर रखा गया है।

यह निर्णय अनाज तिलहन व्यापारी संघ की बैठक में लिया गया। 10 से 17 नवंबर तक दीपावली अवकाश रखा गया है। 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे गणेश मंदिर पर महाआरती कर 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12:33 पर नीलामी मूहर्त रखा गया है।

घुमंतू गौवंश के साथ प्राकृतिक खेतीः वापस खूटों तक लाने की जरूरत

सत्येन्द्र पाल सिंह
कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) म.प्र

गाय बचेगी तो गांव बचेगें और गांव बचेगा तो गरीब बचेगा। जिन्हें आज हम आवारा, घुमंतू, छुट्टा गाय कह रहे हैं कभी यही गायें भारतीय कृषि की रीढ़ रही हैं। भारतीय गायें गांव-गरीब-किसान की पोषण सुरक्षा से लेकर ऊर्जा शक्ति का द्योतक रही हैं। देशी गाय का दूध, दही, छाछ, घी ने जहां भारतीय थाली को पोषण सुरक्षा प्रदान की है वहीं भारतीय गायों के बछड़ों द्वारा जवान होकर खेती में किसान के कमाऊ पूत बनकर उनकी पूरी सेवा की गई है।

मशीनीकरण के दौर और कम उत्पादक होने के कारण भारतीय गायों की नस्लों को हम और आप ने आवारा बनाकर छोड़ दिया है। जोकि आज गांव, खेत, जंगल से लेकर शहरों, महानगरों और सड़कों पर बेबस और लाचार बनकर दर-दर की ठोकरें खाती हुई घूम रहीं हैं। आलम यह है कि कभी जिस किसान को सब कुछ देने वाली भारतीय गाय जो कि गौमाता कही जाती थी, आज उसी किसान की लाठी खाने को मजबूर है। किसान की भी मजबूरी है कि जंगल हैं नहीं और फसलों को भी बचाना है। सड़कों पर महानगरों में यही पूज्यनीय गायें कूड़ा-कचड़ा, पॉलीथीन, गंदगी आदि अपनी उदरपूर्ति के लिए खाने को मजबूर हैं। इसके चलते अधिकांश आवारा घुमंतू गायें बीमार हैं। उनके पेट में पॉलीथीन के गटिठयां जमा हो रही हैं।

कुछ वर्षों पूर्व तक यही गऊमाता अनाधिकृत रूप से कत्लखानों में काटी जा रहीं थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धर्मपरायण सरकारों द्वारा गौहत्या निषेद्ध कानून का कड़ाई से पालन कराये जाने के कारण काफी कुछ हद तक गाय एवं नंदी की क्रूरतम हत्याओं पर पाबंदी लगी है। गौर करें गऊमाता की कत्लखानों में हत्या पर पाबंदी जरूरी लगी है, लेकिन इनके प्रति क्रूरता आज भी जारी है। गांव-शहरों में लाचारी-बेचारी गायों को घायल, बीमार और भूखी-प्यासी बखूबी देखा जा सकता है। घुमंतू गायों के संरक्षण के लिए सरकारों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा काम भी किया जा रहा है। गौशाला में आवारा घुमंतू गौवंश के संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा इन गौशालाओं को अनुदान भी दिया जा रहा है। परंतु गायों की खिलाई-पिलाई, हारी-बीमारी, रखरखाव को देखते हुये यह अनुदान ऊंट के मुहं में जीरे के समान ही है।

आज खेतों से लेकर शहरों-महानगरों और सड़कों पर इन गौवंश के झुण्ड के झुण्ड देखे जा सकते हैं। सरकारों की पहल भी घुमंतू गौवंश को पूरा संरक्षण नहीं दे पा रही हैं। सरकारी प्रयासों से यह पूरी तरह संभव भी नहीं है। इसके लिए आमजन भागीदारी बहुत जरूरी है। आज चारे-दाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आवारा घुमंतू देशी भारतीय गौवंश के संरक्षण के साथ उनसे प्राप्त गौबर और गौमूत्र की ऊर्जा का कैसे सद्उपयोग करें इस दिशा में किसानों को आगे आकर पहल करने की जरूरत है।

इस दिशा में देशी गौ आधारित प्राकृतिक खेती बहुत उत्तम विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आयी है। प्राकृतिक खेती से घुमंतू भारतीय गौवंश के संरक्षण की दिशा में एक नई आशा की किरण जगी है। यदि प्राकृतिक खेती की पहल आम किसान, गांव, खेतों और फसलों तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से देशी भारतीय गायों के दिन अच्छे लाये जा सकते हैं। अब यही समय

है कि प्राकृतिक खेती के लिए घुमंतू गायों को वापस गांव और घर के खूटों तक लाने की जरूरत है।

प्राकृतिक कृषि में एक देशी गाय से 30 एकड़ भूमि पर खेती की जा सकती है। प्राकृतिक कृषि में देशी गाय का गोबर और गौमूत्र मुख्य घटक हैं। देशी गाय के गोबर में करोडों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। यह सूक्ष्म जीवाणु जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति बढाने से लेकर जमीन की जल धारण क्षमता तक को बढाने का कार्य करते हैं। जमीन में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले जीवाणु जमीन को भुरभुरा बनाने से लेकर उसके अंदर वायु स्पेस को बढ़ावा देते हैं, जिससे जमीन धीरे-धीरे उपजाऊ होकर प्राकृतिक रूप से सुदृढ और मजबूत होती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है इसके चलते प्राकृतिक खेती में पैदा होने वाले उत्पाद न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं बल्कि इनसे कई प्रकार के प्राण घातक रोगों से बचा जा सकता है।

देशी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाये जाते हैं जबकि विदेशी अथवा शंकर गाय के एक ग्राम गोबर में केवल 78 लाख सूक्ष्म जीवाणु पाये जाते हैं। देशी गाय के गोबर एवं मूत्र की महक से देशी केंचुए भूमि की सतह पर आ जाते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ये 16 तत्व ही हमारे पौधों के विकास के लिए उपयोगी हैं। इन्हीं 16 पोषक तत्वों को पौधे भूमि से लेकर अपना विकास करते हैं। यह सभी 16 पोषक तत्व देशी गाय की आंत में निर्मित होते हैं, इसलिए देशी गाय प्राकृतिक कृषि की मूलाधार है। प्राकृतिक कृषि गौ आधारित अर्थात देशी गाय आधारित कृषि है। कह सकते हैं कि प्राकृतिक कृषि के माध्यम से देशी गाय की रक्षा की जा सकती है।

प्राकृतिक कृषि में आवारा घुमंतू देशी गाय का महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। बताया जाता है कि घुमंतू देशी गाय के गोबर में पालतू देशी गाय से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाये जाते हैं। ऐसे किसान जिनके पास आज देशी गाय नहीं हैं वह भी घुमंतू देशी गाय को पकड़कर प्राकृतिक खेती की शुरूआत कर सकते हैं। इससे जहाँ घुमंतू देशी गायों को नया जीवनदान मिलेगा साथ ही उन्हें भरपेट चारा भी मिल सकेगा। इस प्रकार से किसान की आमदनी में इजाफा होने के साथ ही उनके खेतों की मिट्टी की दशा और दिशा में सुधार होगा। किसानों का इस प्रकार का कदम देशी गाय की रक्षा के साथ ही प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देगा। इसलिए किसानों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने के साथ ही इसे जितनी जल्दी हो सके अपनाने की जरूरत है।

व्यवसायिक सूकर प्रक्षेत्र में होने वाले प्रबंधन क्रियाकलाप

» डॉ. सुलोचना सेन
» डॉ. राजेश वांद्रे
» डॉ. अभिलाषा सिंह
» डॉ. सुमन संत
» डॉ. बालेश्वरी दीक्षित
» डॉ. अनीता तिवारी
-पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग
पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विस्तार शिक्षा विभाग, पशुजन स्वास्थ्य विभाग

सूकर का उत्पादन किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह है बिना स्पष्ट उद्देश्यों और उत्पादन लक्ष्यों के कम लाभदायक हो सकता है। सूकर पालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सूकर के उत्पादन और प्रदर्शन पर विचार करना चाहिए, अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के तरीकों की पहचान करनी चाहिए, सुकरो को उपयुक्त आवास प्रदान करना चाहिए एवं उम्र अनुसार उचित भोजन का प्रबंधन करना चाहिए और पर्यावरणीय मुद्दों की निगरानी करनी चाहिए। सूकर पालन से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आधुनिक और सुस्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों प्रथाओं और कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए।

सूकरपालन से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख मानदंड और अनुशंसित अभ्यास नीचे दिए गए हैं:

आवास प्रबंधन: सूखी और ठीक से उठी हुई जमीन पर शेड का निर्माण करें। जल-जमाव, दलदली और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से बचें। शेड की साइड की दीवारें 4-5 फीट ऊंची होनी चाहिए और बाकी की ऊंचाई जीआई पाइप या लकड़ी के खंभों से फिट होनी चाहिए। छत कम से कम 8-10 फीट ऊंची होनी चाहिए। सूकर की शैली अच्छी तरह हवादार होनी चाहिए। फर्श पक्का कठोर, सम, गैर-फिसलन, अभेद्य, अच्छी तरह से ढलान (3 सेमी प्रति मीटर) होना चाहिए। प्रति सूकर 6-12 इंच का चारा गर्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक जानवर के लिए पर्याप्त खुला स्थान प्रदान करें अर्थात ढके हुए क्षेत्र को दोगुना करें। सूअर स्तनपान कराने वाली बोने के लिए अलग-अलग कलमों का निर्माण किया जाना चाहिए। ड्राई साउ को ग्रुप पेन में रखा जा सकता है। पशुओं के लिए पर्याप्त जगह दें।

ब्रीडर स्टॉक का चयन: ऋण जारी होने के तुरंत बाद, एक विश्वसनीय ब्रीडर या निकटतम पशुधन बाजार से स्टॉक खरीद लें। व्यावसायिक सूकर पालन के लिए उन्नत क्रॉस ब्रीड या अच्छे स्वास्थ्य में विदेशी स्टॉक का चयन किया जाना चाहिए। गिल्ट या सोव का चयन करते समय या बोना प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसी मादा को सुरक्षित करना होना चाहिए जो बड़े जीवित लित्तेर का उत्पादन करे और जो छह महीने या उससे कम उम्र में मर्केट योग्य वजन प्राप्त कर सके। यह वंशावली अभिलेख पशु चिकित्सक बैंक के तकनीकी अधिकारी की सहायता से किया जा सकता है। ऐसे पशु खरीदें जो प्रजनन के लिए तैयार हों। उपयुक्त पहचान चिह्न देकर नए खरीदे गए जानवर की पहचान करें। नए खरीदे गए पशुओं का रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करें। झुंड में पशुओं को विवेकपूर्ण तरीके से पालने और बदले जाने का पालन करें। 10-12 फरोइंग के बाद पुराने जानवरों को कल करें।

आहार प्रबंधन: पशुओं को सर्वोत्तम आहार खिलाएं। राशन में पर्याप्त मात्रा में सांद्रण दें। पर्याप्त विटामिन और खनिज प्रदान करें। पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। पशुओं को पर्याप्त व्यायाम दें। सूकरों को खिलाना अधिक महत्वपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाला होता है और उन्हें खिलाने के लिए अधिक दृढ़ आहार की आवश्यकता होती है।व्यावसायिक सूकर पालन का लक्ष्य उत्पादन की लागत को कम करने के लिए संतुलित राशन के स्थान पर गैर-पारंपरिक फीड संसाधनों अर्थात रसोई होटल कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस से निकलने वाले कचरे का दोहन करना चाहिए। अपनाई गई आहार व्यवस्था में सुअरों की विभिन्न श्रेणियों की सभी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए जो निम्नानुसार होना चहिये।

दैनिक आहार की मात्रा: ग्रोअर सूकर (26 से 45 किलो तक): प्रतिदिन शरीर वजन का 4 प्रतिशत अथवा 1-5 से 2-0 किलो दाना मिश्रण। **ग्रोअर सूकर** (वजन 12 से 25 किलो तक)= प्रतिदिन शरीर वजन का 6 प्रतिशत अथवा 1 से 1-5 किलो ग्राम दाना मिश्रण। **फिनसर सूकर**= 2-5 किलो दाना मिश्रण। **प्रजनन हेतु नर सूकर:** 3-0 किलो। **गाभिन सूकरी:** 3-0 किलो। **दुधारू सूकरी:** 3-0 किलो और दूध पीने वाले प्रति बच्चे 200 ग्रा. की दर से अतिरिक्त दाना मिश्रण- अधिकतम 5-0 किलो। दाना मिश्रण को सुबह और अपराहन में दो बराबर हिस्से में बाँट कर खिलायें। गर्भवती एवं दूध देती सूकरियों को भी फिनिशर राशन ही दिया जाता है।

रोगों से बचाव: बीमारी के लक्षणों जैसे कम भोजन का सेवन, बुखार, असामान्य निर्वहन या असामान्य व्यवहार के लिए सतर्क रहें। रोगी पशु की देखभाल करने वाले व्यक्ति को हाथ पैर जन्तूनाशक दवाई से धोकर स्वस्थ पशु के पास जाना चाहिए । रोगी पशुओं के मलमूत्र में दूषित कीटाणु रहते हैं, अत: गर्म रख या जन्तु नाशक दवा से मलमूत्र में रहने वाले कीटाणु को नष्ट करना चाहिए। अगर कोई पशु संक्रामक रोग से मर जाए तो उसकी लाश को गढ़े में अच्छी तरह गाड़ना चाहिए। बीमारी का संदेह होने पर मदद के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा सहायता केंद्र से संपर्क करें। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जानवरों को समय-समय पर धोएं।

प्रजनन देखभाल: सूकर अत्यधिक उर्वर प्रकृति के होते हैं और उचित प्रबंधन स्थितियों को अपनाकर एक वर्ष में दो फरोइंग की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक 10 सोव के लिए अधिकतम उर्वरता के लिए एक सूअर को बनाए रखना चाहिए। पशुओं को तब प्रजनन करें जब यह अत्यधिक गर्मी की अवधि (अर्थात 12 से 24 घंटे की गर्मी) में हो।

गर्भावस्था के दौरान देखभाल: पर्याप्त जगह, चारा, पानी आदि उपलब्ध कराकर एक सप्ताह पहले गर्भवती सोव पर विशेष ध्यान दें। फरोविंग पेन के को फैरोइंग की अपेक्षित तिथि से 3-4 दिन पहले कीटाणुरहित कर देना चाहिए और सोव को फैरोइंग पेन में रख देना चाहिए।

पराली बन सकती है किसान की कमाई का साधन

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई गई पराली से उठते धुएं ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। वैज्ञानिक अब पराली के सही उपयोग के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने पराली से बायो थर्मोकॉल बनाने में सफलता हासिल की है। इस तकनीक से प्रोडक्ट बनाने के लिए अब बाकायदा एक औद्योगिक इकाई से एमओयू भी हो चुका है।

आईसीआर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद कसाना ने बताया कि धान और गेहूं की पराली से आसानी से बायो थर्मोकोल तैयार किया जा सकता है। इसे तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। पराली से तैयार किया गया बायो थर्मोकोल रसायन से बनाए गए थर्मोकोल की तरह ही हल्का होता है लेकिन यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल यानी कुदरती तौर पर नष्ट हो सकता है। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। केमिकल से बनाए गए थर्मोकोल के इस्तेमाल से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है क्योंकि यह कुदरती तौर पर नष्ट नहीं होता। वैज्ञानिक अब इसे छत की सीलिंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भवन निर्माण में भी पराली को इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसान पराली को ना जलाएं, इसके लिए वैज्ञानिक और राज्य सरकारें पराली के इन-सीटू और एक्स -सीटू प्रबंधन यानी पराली को खेत में ही या फिर खेत के बाहर इस्तेमाल करने के तरीकों पर काम कर रही हैं। अकेले पंजाब में 7.5 मिलियन एकड़ क्षेत्रफल पर धान की फसल उगाई जाती है, जिससे हर साल 22 मिलियन टन पराली पैदा होती है। सरकार का दावा है कि 60 फ़ीसदी पराली यानी 12 मिलियन टन पराली को खेतों में ही नष्ट करने के प्रयास किया जा रहे है। एक अनुमान के मुताबिक, पंजाब में हर साल 10 मिलियन टन पराली जला दी जाती है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, पराली का 34 फ़ीसदी हिस्सा जानवरों के चारे के रूप में और 43 फ़ीसदी हिस्सा खेतों में ही नष्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि राज्य में 23 फ़ीसदी पराली का प्रबंधन एक्स सीटू तरीके से हो रहा है। राज्य के दो दर्जन के करीब उद्योग पराली को अब ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अबकी बार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 50 फ़ीसदी से ज्यादा गिरावट आई है। राज्य सरकारों का दावा है कि पराली जलाने के मामलों में आई गिरावट कुशल पराली प्रबंधन का नतीजा है। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ने भी पराली जलाने के मामलों में 53 फ़ीसदी तक गिरावट की पुष्टि की गई है।

हालांकि, नासा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन राज्यों में अभी भी आधी से ज्यादा पराली आग के हवाले की जा रही है लेकिन इस बीच आईसीआर के वैज्ञानिकों ने पराली का इस्तेमाल बायो थर्मोकोल के रूप में करके एक तरफ जहां पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया है, वहीं किसानों को अपनी आय बढ़ाने का भी मौका दिया है।

बोवनी मुख्य रूप से 15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक करें किसान

सरसों की उन्नत किस्मों की दूरी पर करें बोवनी

सागर। जागत गांव हमार

रबी फसलों की बुआई समय आ गया है किसानों द्वारा जिले में गेहूं ,चना, मसूर आदि मुख्य फसलों के अतिरिक्त सरसों की खेती भी मुख्य तौर पर धीरे-धीरे किसानों द्वारा ली जाने लगी है। सरसों की बुआई मुख्य रूप से 15 अक्टूबर से लेकर 5 से 10 नवंबर तक कर सकते हैं।

अच्छे उत्पादन के लिए सरसों की उन्नत किस्में- उन्नत किस्मों के रूप में वर्तमान में प्रमुख रूप से अधिक ऊपज देने वाली किस्मो में गिरिराज, जवाहर सरसों 2, जवाहर सरसों 3, राज विजय सरसों 2, पूसा अग्रणी , पूसा सरसों 28, आरएच 749, आरएच 725 , पूसा बोल्ड, वरुणा, माया , आशीर्वाद, इत्यादि लगा सकते हैं। जिनकी औसत उपज क्षमता सिंचित अवस्था में 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक पाई जाती है। लगाने का उत्तम समय अक्टूबर माह होता है परंतु 5 नवंबर तक इसे लगा सकते हैं।

बीज उपचार और मात्रा- प्रति एकड़ बीज दर 2 से 2.5 किलो रखना चाहिए। बुवाई के पूर्व कार्बेंडाजिम या वेविस्टीन नामक कवकनाशी दवा से 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। बुवाई सीड ड्रिल की सहायता से करना चाहिए। छोटे बीजों के कारण इसमें 10 से 12 किलो डीएपी मिलाकर बुआई कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी 08 से 10 सेंटीमीटर तथा पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए।

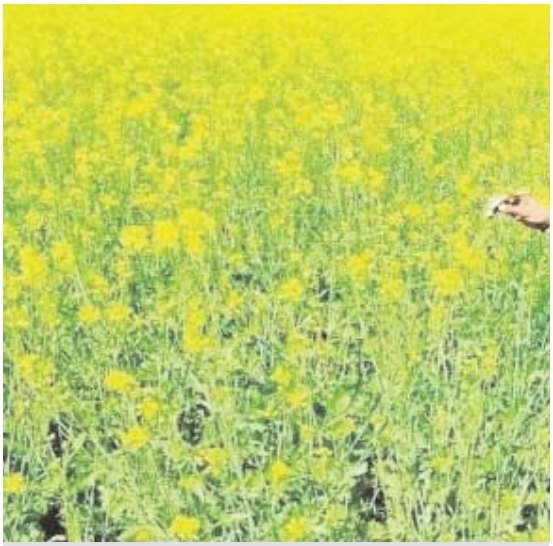

खरपतवार नियंत्रण

सरसों के लिए यदि पलेवा कर बुवाई कर रहे हो तो नमी की अवस्था में पेंडामेथिलीन 30प्रतिशत दवा की 1. 25 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति ऐकर खेत के ऊपर बुआई के दो से तीन दिन के भीतर अर्थात अंकुरण से पूर्व छिड़काव करने से 20 से 25 दिन तक खरपतवार नही उगता है, तदुऊपरांत एक या दो बार सिंचाई उपरांत कुल्पा साइकिल हैंड हो आदि चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए।

कब दें उर्वरक और कितना

ध्यान रखें की बीज की गहराई दो से ढाई सेंटीमीटर से अधिक नहीं जाना चाहिए। इसके लिए चाहे तो सीड ड्रिल के आगे के पोरों या नलियों को बंद कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग वैसे तो उवज़रकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के बाद ही करना चाहिए। परंतु सामान्य तौर पर उत्तम विकल्प के रूप में सिंचित खेती के लिए अर्थात जहां तीन से चार पानी उपलब्ध हो वहां पर प्रति एकड़ यूरिया की मात्रा 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट अर्थात एस एस पी की मात्रा 50 किलो तथा पोटाश की मात्रा 5 से 6 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए।

सिंगल सुपर फास्फेट देने से सल्फर अर्थात गंधक की पूर्ति के साथ-साथ कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है, जो तेल बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि विगत तीन वर्षों में भूमि में जिंक सल्फेट नहीं दे पाए हो तो जिंक सल्फेट 33 प्रतिशत की 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से खेत में देना चाहिए। यदि आपके पास गोबर की खाद या केंचुआ खाद उपलब्ध हो तो प्रति एकड़ 50 से 60 कुंतल गोबर की खाद या 20 कुंतल केंचुआ खाद दे सकते हैं। देने का तरीका यूरिया की आधी मात्रा एवं शेष सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा को खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के समय छिड़क कर पूरे खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष बची यूरिया की 25 किलो मात्रा को 25 से 30 दिन बाद सिंचाई उपरांत देना चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध न हो तो इसके स्थान पर डीएपी के रूप में 18 किलो डीएपी प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए।

अर्धसंचित अवस्था अर्थात दो पानी उपलब्ध होने पर प्रति एकड़ यूरिया की 35 किलोग्राम मात्रा, एसएसपी की 50 किलोग्राम मात्रा और पोटाश की 4 से 5 किलोग्राम मात्रा तथा जिंक सल्फेट की 5 किग्रा मात्रा प्रति एकड़ देना चाहिए। जहां एस एस पी उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर डीएपी की मात्रा प्रति एकड़ 18 किलो दे सकते हैं। उपरोक्ता अनुसार यूरिया की आधी मात्रा को तथा शेष उर्वरकों की पूरी मात्रा को खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। शेष बच्ची 17.5 किलो यूरिया को प्रथम सिंचाई उपरांत दिया जाता है।

जलवायु समुत्थानुशील कृषि में राष्ट्रीय नवाचार परियोजना

वैज्ञानिकों की देखरेख में एकीकृत कृषि प्रणाली से आगे बढ़ रहा ग्राम कोड़िया

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में डॉ. आरके प्रजापति वैज्ञानिक एवं जयपाल छिगारहा द्वारा निकारा परियोजना अंतर्गत अंगीकृत ग्राम कोड़िया में एकीकृत कृषि प्रणाली द्वारा कृषक परिवारों व उनके अंतर्गत आने वाली सभी संसाधनों का समन्वित रूप से दोहन इस तरह उपयोग किए जाने पर कार्य कर रहे हैं कि किसान की घरेलू जरूरतें पूरी होने के साथ-साथ अधिक आमदनी प्राप्त हो तथा दूसरी फसल व पशु अवशेषों के पुन: चक्रण द्वारा टिकाऊ फसलों उत्पादन में सहायक हो। साथ ही भोजन एवं चारे की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी और जमीन, पानी, श्रम और कृषि जोत कम होती जा रही है। मृदा में पोषक तत्वों का ह्रास होता जा रहा है भोजन का स्तर घटता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है और छोटे व सीमांत किसानों के लिए कृषि घाटे का व्यवसाय बनता जा रहा है। एकीकृत कृषि प्रणाली में कृषि उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन आदि को इस प्रकार सम्मिलित किया जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कृषि में किया जा सके। इस प्रणाली से लघु व सीमांत किसानों की आजीविका में वृद्धि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कृषि अवशेषों का पुन: उपयोग वर्ष भर आमदनी के विकास, जलाऊ लकड़ी एवं चारे की व्यवस्था, छोटे उद्योगों जिससे कि कृषकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कोड़िया में इस प्रकार से उन कृषि नवीन तकनीकियों पर काम किया जा रहा है, जैसे पशुओं में नस्ल सुधार, मुर्गी पालन को बढ़ावा, वर्मी कंपोस्ट, पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा, सब्जियों एवं फलों में उन्नत जलवायु सहनशील किस्मों को लगवाना, रबी एवं खरीफ की फसलों में उन्नत किस्म का कृषकों को प्रदर्शन द्वारा प्रेरित करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे गोबर, खेत का कचरा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस आदि के लिए कृषकों को प्रेरित करना। वैज्ञानिकों का दल जिले में अन्य विभागों के साथ जैसे कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग मछली पालन, एवं मनरेगा परियोजना से गांव में भ्रमण करके योजना बनाकर काम कर रहे हैं।

छात्रों को वैज्ञानिकों ने बताया

खेती इस तरह बनाएं लाभ का धंधा

छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव के कृषि से (11 एवं 12) के 35 अध्यनरत छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हुए, जिसमे डॉ. वीणापाणी श्रीवास्तव (प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख) ने सभी छात्रों को बताया कि छात्र जीवन में कैसे रहना है और किस प्रकार से सतर्क रहना है। साथ ही कृषि को कैसे लाभ का धंधा बनाना है विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी) के द्वारा सभी छात्रों को कृषि के क्षेत्र में बढ़ने वाले महत्व को विस्तार से बतलाया साथ ही छात्रों को अपने कैरियर को बनाने में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। हेमन्त कुमार सिन्हा (मौसम वैज्ञानिक) ने भी सभी छात्रों को बताया कि मौसम का कृषि पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। उसको विस्तार से अवगत कराया गया आज के इस कार्यक्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आचार्य राजेश अहिरवार एवं शैलेंद्र साहू भी उपस्थित रहे कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में प्रदर्शित नर्सरी इकाई एवं फलोत्पादन पपीता प्रदर्शन इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया।

मुरैना में गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का आयोजन

मुरैना। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र , मुरैना द्वारा प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ आरकेएस तोमर के निर्देशन में अक्टूबर माह में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अंतर्गत गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का आयोजन केंद्र के साथ ही विभिन्न ग्रामों में किया गया। डॉ. तोमर ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि भूमि, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए वृक्षारोपण करें, ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके। यह कार्यक्रम ग्राम गढ़ीखेरा, खोह का पुरा, पिपरसेवा, खेरा का पुरा आदि में किया गया। जिसमें करीब 382 कृषक, कृषक महिलाएं एवं स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ रीता मिश्रा ने स्वच्छता एवं पोषण की जानकारी देते हुए कहा कि हम खानपान में सफाई का विशेष ध्यान रखकर बहुत से पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी अधिकारी अर्चना ने कहा कि भोजन से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। डॉ स्वाति सिंह तोमर ने गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग करने से भी आसपास स्वच्छता रखी जा सकती है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ एस .वीएस चौहान, डॉ अशोक सिंह यादव, डॉ. पीकेएस गुर्जर, डॉ. बीएस कसाना, रीना शर्मा, देवेश सिंह के साथ ही कृषि महाविद्यालय ग्वालियर की छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मुख्य कार्यक्रम 10 नवंबर को हरियाणा के पंचकूला में आयोजित किया जाएगा

देशभर के किसान बन रहे 'आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ' अभियान का हिस्सा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

आयुर्वेद दिवस के तहत देश के किसान 'आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ'अभियान से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। 'किसानों के लिए आयुर्वेद' कार्यक्रम के तहत उन्हें आयुवेज्द चिकित्सा में उपयोग होने वाली जड़ी बूटियों और पौधों की खेती के गुणों से अवगत कराया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम 10 नवंबर, 2023 को हरियाणा के पंचकूला में आयोजित किया जाएगा।

देश भर के किसान इस आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं और औषधीय पौधों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद अभियान के तहत, देश भर के किसानों को बैठकों, परस्पर वार्ताओं, कार्यक्रमों और संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करके संवेदनशील बनाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी (केंद्रीय अनुसंधान परिषद) द्वारा एक माइक्रो वेबसाइट विकसित की गई है। विश्व भर के आगंतुक 'आयुर्वेद दिवस' के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं और एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद अभियान से संबंधित विभिन्न चल रही गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद दिवस को सद्धक्त्र बनाने में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। छात्रों और युवाओं के अतिरिक्त देश भर के किसानों को आयुर्वेद दिवस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

देशभर से किसानों को समूह बैठकों, व्यक्तिगत परस्पर वार्ताओं, व्याख्यान और कार्यशालाओं के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। देश भर में स्थित सात आरसीएफसी (क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र) और 37 एसएमपीबी (राज्य औषधीय पादप बोर्ड) किसानों को 'आयुर्वेद दिवस' अभियान से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इन केंद्रों से जुड़े सहयोगी घर-घर जाकर किसानों को औषधीय पौधे वितरित कर रहे हैं और किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय से जुड़े सभी संस्थान और विभिन्न मंत्रालयों की टीमें आयुर्वेद दिवस को वैश्विक आयोजन के रूप में मनाने की निरंतर तैयारी कर रही है।

किसानों की आय डबल करने में भी इफ्को की भूमिका अहम रही

आज देश के प्रधानमंत्री के मिशन किसानों की आय को दुगुना करने में भी इफ्को की भूमिका अहम रही है। दरअसल, इफ्को एक उर्वरक उत्पादक कंपनी है। कृषि क्षेत्र में फसलों को अच्छी पैदावार के साथ ही यह उनकी गुणवत्ता के मानकों पर भी पुरी तरह से खरा उतरा है। जिसके परिणाम स्वरुप किसानों के विश्वास को हम आज भी कायम रख पाए हैं।

समय के साथ बढ़ता रहा उत्पादन

देश में इफ्को की मांग और उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ते रहे। इसका प्रमुख कारण फसलों के लिए प्रभावी और सुरक्षित उर्वरक को उपलब्ध कराना था। इसी सुरक्षित उपलब्धता ने किसानों के बीच हमारे प्रति विश्वास को बढ़ाया, जिसके चलते देश में इफ्को की मांग और विश्वास दोनों निरंतर बढ़ते रहे।

देश में किसानों की आय दोगुनी मिशन का साथी इफ्को

पिछले 56 वर्षों में, इफ्को उत्पादों, सेवाओं और समर्थन प्रणालियों वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और टिकाऊ प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। कृषि क्षेत्र में निरंतर किसानों देने वाली देश की अग्रणी कंपनी इफ्को ने आज अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत की हरित क्रांति में उर्वरकों की अहम् भूमिका रही है। जिसमें इफ्को स्थापना के बाद से ही लगातार कृषि और किसानों के बीच अपने विश्वास को कायम रखने और किसानों की फसलों को ज्यादा पैदावार की दिशा में एक सहयोगी के रूप में साथ रहा है। इफ्को आज दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था के रूप में खड़ी, 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना किसानों को गुणवतापूर्ण उर्वरकों के उत्पादन में मदद करने के लिए की गई थी।इफ्को से जुड़ी सहकारी समितियों की संख्या 1967 में 57 से बढ़कर वर्तमान में 39,800 से अधिक हो गई है। आज देश के लगभग सभी किसान इफ्को से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। किसानों के इसी विश्वास के चलते आज हम कृषि क्षेत्र में सबसे अग्रणी उर्वरक उत्पादक के रूप में अपनी जगह बना पाए हैं।

गाय अपने जीवनकाल में 6 से 12 बच्चों को दे सकती है जन्म

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केवल गिर गायों की नस्ल को दिया जा रहा प्रोत्साहन

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

देश के किसान आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन भी करते हैं। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है ताकि डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इस योजना को 2025 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था।

स्वदेशी मवेशियों की नस्लों में सुधार के लिए भारत की प्रमुख योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लगभग एक दशक बाद, देश में एक अजीब बाधा उत्पन्न हुई है। जैसा कि योजना के तहत कल्पना की गई थी, सभी स्वदेशी नस्लों की गुणवत्ता में सुधार करने के बजाय, इसने देश भर में केवल एक स्वदेशी किस्म, गिर गाय को बढ़ावा दिया है। यदि इस प्रवृत्ति को ठीक नहीं किया गया तो देश भर में स्वदेशी नस्लों की शुद्धता को खतरा हो सकता है। देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए बीते कई सालों से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ताकि स्वदेशी मवेशियों की नस्लों में सुधार की जा सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जिसमे से एक है गोकुल मिशन। वहीं इस मिशन में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के मुताबिक गोकुल मिशन के तहत अब केवल गिर गाय को बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना

इस देश के किसान आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन भी करते हैं। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है ताकि डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इस योजना को 2025 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गायों और दुधारू पशुओं की देशी नस्लों में सुधार करना था। इस योजना का उद्देश्य देशी नस्लों को बढ़ावा देना और इन पशुओं में होने वाली विभिन्न घातक बीमारियों से बचाना है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि सरकार गोकुल मिशन के तहत केवल गिर गाय को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि गिर प्रजाति की गाय दूध उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों के लिये ज्यादा अनुकूल है। जिस वजह से सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।

गिर गाय की पहचान| गिर नस्ल की गाय गुजरात के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। यह नस्ल मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ब्राजील तक प्रसिद्ध है. इसे देसन, गुजराती, सुरती, काठियावाड़ी और सोरठी भी कहा जाता है। इनका शरीर आमतौर पर लाल रंग का होता है और उस पर सफेद धब्बे होते हैं। गिर गाय का सिर गुंबद के आकार का और कान लंबे होते हैं। इसका जीवनकाल लगभग 12 से 15 वर्ष का होता है। इनका वजन लगभग 400-475 किलोग्राम हो सकता है। यह गाय अपने जीवनकाल में 6 से 12 बच्चों को जन्म दे सकती है।

गिर नस्ल की गायों में हुई गिरावट!

वर्ष 2019 में आयोजित पशुधन जनगणना के अनुसार, वर्ष 2013 के बाद से गिर नस्ल की गायों में 70प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इसके विपरीत, साहीवाल और हरियाणा जैसी अन्य स्वदेशी नस्लों में समान वृद्धि नहीं देखी गई। वहीं कुछ नस्लों की संख्या में गिरावट भी देखी गई। जिस वजह से अब गिर गायों के नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

किसान प्रमाणित बीज वितरण अनुदान राशि का लाभ उठाएं

बड़वानी। जागत गांव हमार

जिले में रबी सीजन प्रारंभ हो चुका है। किसानों को अवगत कराया जाता है कि सहकारी संस्थाओं व बीज संघ समितियों में रबी के लिए प्रमाणित बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसानों से अपील है कि रबी बीज खरीद कर प्रमाणित बीज वितरण अनुदान राशि का अधिक से अधिक लाभ लेवें। उल्लेखनीय है कि रबी वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा प्रमाणित बीज वितरण अनुदान पर गेहूं (10 वर्ष तक की अवधि) वाली किस्म 1000 प्रति क्विंटल, चना (10 वर्ष तक की अवधि) वाली किस्म 3300 प्रति क्विंटल, चना (10 वर्ष से अधिक अवधि) वाली किस्म

2500 प्रति क्विंटल, मसूर (10 वर्ष तक की अवधि) वाली किस्म 3850 प्रति क्विंटल, मसूर (10 वषज से अधिक अवधि) वाली किस्म 2500 प्रति क्विंटल, सरसों (15 वषज तक की अवधि) वाली किस्म 4000 प्रति क्विंटल, अलसी (15 वर्ष तक की अवधि) वाली किस्म पर 4000 प्रति क्विंटल अनुदान है।

वर्मी कंपोस्ट खादः सरकार दे रही 50 फीसदी अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं फसल उत्पादन की लागत कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जैविक खाद बनाने के लिए किसानों को अनुदान भी उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए भारी अनुदान उपलब्ध करा रही है। ऐसे में जो किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन का भी काम कर रहे हैं वे किसान योजना का लाभ लेकर जैविक खाद इकाई की स्थापना कर सकते

हैं। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती के साथ पशुपालन करते हों। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लाभार्थी किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति इकाई दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान दिया जाएगा।

ये किस्में देती हैं 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार

फ्रेंचबीन की खेती में ज्यादा पैदावार और अच्छा फायदा

सब्जी और सूखे दाने का प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है..

भोपाल। जागत गांव हमार

फ्रेंचबीन का दलहनी फसलों के कुल में प्रमुख स्थान है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती सर्दियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में की जाती है। दक्षिण भारत में इसकी खेती वर्षभर की जाती है। फ्रेंचबीन की हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में तथा सूखे दाने का प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है। अन्य सब्जी फसलों की तुलना में यह कम अवधि में अधिक उपज देने वाली फसल है। फ्रेंचबीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, केरोटीन व फोलिक अम्ल का अच्छा स्त्रोत होता है।

फ्रेंचबीन की उन्नत किस्में

कन्टेंडर: यह किस्म मोजेक एवं चूर्णिल आसिता के प्रति सहिष्णु है। इसकी पैदावार 190 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

पूसा पार्वती: यह किस्म मोजेक एवं चूर्णिल आसिता के प्रति अवरोधी किस्म है। उत्पादन 80-85 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

अर्का सुविधा: यह किस्म ब्लू क्रॉप व कन्टेंडर संकरण उपरांत वंशावली चयन विधि से विकसित की गई है। पैदावार 190 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

अर्का कोमल: इस किस्म की फलियां दूरस्थ स्थानों को भेजने व लम्बे समय तक रखने के लिए उपयुक्त होती हैं। उत्पादन 70-80 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

स्वर्णप्रिया: इस किस्म के पौधे झाड़ीनुमा, फलियां गोल, गूदेदार तथा हरे रंग की होती है। उत्पादन 120-140 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

पंत अनुपमा: इस किस्म के पौधे छोटे झाड़ीनुमा, सीढ़ी बढ़वार वाले तथा फलियां चिकनी, मुलायम, गोल हरे रंग की रेशारहित होती हैं। यह कोणीय पर्ण धब्बा के प्रति रोगरोधी तथा सामान्य बीन मोजेक वायरस के प्रति सहनशील किस्म है। उत्पादन 70-80 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

काशी परम: इस किस्म की फलियां 10-12 से.मी. लम्बी, गोल व गूदेदार तथा हरे रंग की होती है। उत्पादन क्षमता 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

काशी राजहंस: यह बौनी किस्म है जिसका उपयोग केवल सब्जी के लिए किया जाता है। इस किस्म के पौधों में 30-32 तापक्रम पर भी फलत होती है। उत्पादन 210 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

काशी सम्पन्न: यह बौनी किस्म है जिसका उपयोग केवल सब्जी के लिए किया जाता है। यह येलो मोजेक वायरस के प्रति अवरोधी किस्म है। उत्पादन 234 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

पूसा हेमलता: इस किस्म के पौधे चढ़ने वाले मध्यम उंचाई (2.5 मीटर) तथा फलियां मध्यम लम्बी (14 से.मी.), गोल गूदेदार, रेशारहित तथा हल्के हरे रंग की होती है।

स्वर्णलता: यह शुद्ध पंक्ति चयन द्वारा विकसित किस्म है जिसके पौधे चढ़ने वाले, फलियां गोल, गूदेदार, रेशारहित अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। उत्पादन 100 से 125 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।

जलवायु

फ्रेंचबीन मुख्यतः गर्म जलवायु की फसल है। इसकी अच्छी बढ़वार तथा उपज के लिए 18-24 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान उपयुक्त होता है। फ्रेंचबीन की फसल अधिक गर्मी और सर्दी (पाला) के प्रति संवेदशील होती है। तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेट से कम तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक, फसल की वृद्धि एवं उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

भूमि का चुनाव व तैयारी

फ्रेंचबीन की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परन्तु उचित जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई-दोमट मिट्टी से लेकर बलुई मिट्टी जिसका पी.एच. मान 6-7 के मध्य हो, उचित रहती है। इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि उपयुक्त नहीं होती है। यदि खेत में नमी कम हो तो बुवाई से पूर्व पलेवा कर लेना चाहिए। बुवाई से पूर्व खेत की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। बुवाई के समय बीज अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।

बीज दर

झाड़ीदार किस्म: 80-90 किग्रा बीज/हेक्टेयर

बेलदार किस्म: 25-30 किग्रा बीज/हेक्टेयर

बीज बुवाई: उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फ्रेंचबीन की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर-नवंबर तथा तराई क्षेत्रों में फरवरी-मार्च होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में फ्रेंचबीन की खेती ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में की जाती है। बीज की बुवाई समतल खेत में या उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में की जाती है। उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में बुवाई करने से पौधों की वृद्धि भली भांति होती है तथा उपज भी अच्छी होती है। झाड़ीनुमा (बुश टाइप) किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 45-60 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेमी तथा लता वाली (पोल टाइप) किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 75-100 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 25-30 सेमी रखते हैं।

बैंगन की उन्नत खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

भोपाल। बैंगन की खेती एक साल में तीन बार की जा सकती है। यदि उन्नत तकनीक के साथ बैंगन की खेती की जाए तो किसानों के लिए काफी लाभकारी हो सकती है। बैंगन में लौह, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए-बी-सी भी होते हैं। बैंगन मुख्य रूप से सब्जी के लिए खेती की जाती है। बैंगन नर्सरी तैयार करने के लिए जून-जुलाई और रोपाई के लिए जुलाई-अगस्त अच्छे समय है। बैंगन की फसल को उचित जल निकास और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए।

खेत की तैयारी- पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, उसके बाद 3-4 बार हैरो या देशी हल चलाकर पाटा लगाएं। रोपाई से दस से पंद्रह दिन पहले खेत में सड़ी गोबर की खाद मिलानी चाहिए। प्रति हेक्टेयर 120 ग्राम नत्रजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 80 ग्राम पोटाश मिलाकर अंतिम जुताई में आधी नत्रजन, पूरी फास्फोरस और पोटाश मिलाना चाहिए।

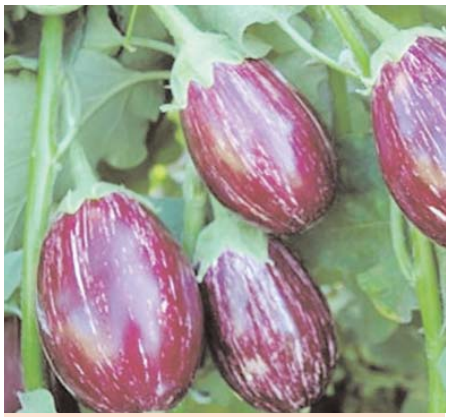

नर्सरी तैयार करना

एक हेक्टेयर बैंगन की फसल के लिए 400-500 ग्राम बीज व संकर प्रजातियों का 300 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। बुवाई से पहले बीज को ट्राइकोडरमा से इलाज करें। जहां नर्सरी बनानी है, वहां अच्छी तरह से खुदाई करें, खरपतवारों को निकालें और सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। जिससे जमीन में जीवांश पर्याप्त मात्रा में रहे। 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडमर प्रति वर्ग मीटर में मिलाकर भूमि जनित रोगों को मार डालें। 15 से 20 क्यारियां (एक मीटर चौड़ी और तीन मीटर लंबी) पौध तैयार करने के लिए बनाई गईं। बीज को पांच सेमी की दूरी पर एक सेमी की गहराई पर पंक्ति में बुवाई करें।

रोपण

12-15 सेमी लंबी चार पत्तियों वाली पौध रोपाई के लिए उपयुक्त है। शाम को रोपाई करनी चाहिए। पौधे से 60 गुणा 60 सेमी की दूरी रखनी चाहिए। रोपाई करने के बाद हल्की वर्षा करें। फसल को हर 12-15 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की समाप्ति से पहले निराई-गुड़ाई करें।

उत्पादन और तुड़ाई

फल को तोड़ना चाहिए जब वे पूर्ण आकार व रंग प्राप्त कर लें। बैंगन की उपज मौसम और प्रजाति पर निर्भर करती है। 250-500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज प्राप्त की जा सकती है।

काले गेहूं की खेती से किसान बन सकते हैं अमीर, जानें खासियत

भोपाल। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई कुछ ही दिनों में शुरू भी हो जाएगी। ज्यादातर किसान पारंपरिक गेहूं की फसल की बुवाई करते हैं। हालांकि, इस बीच किसान अलग-अलग किस्मों की फसल की खेती में अपनी रूचि दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कई किसान काले गेहूं की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। काले गेहूं की मार्केट में अच्छी डिमांड भी और यह बाजार में लगभग 8000 रुपए क्विंटल में बिकता है।

स्वास्थ्य के लिए बेहतर काला गेहूं: काले गेहूं की कीमत भी सामान्य गेहूं से ज्यादा होती है। काले गेहूं में सामान्य गेहूं की तुलना में 60प्रतिशत अधिक लौह तत्व होता है। गेहूं का काला रंग इसमें मौजूद एंथोसायनिन नामक रंगद्रव्य के कारण होता है। इस किस्म में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। काले गेहूं की खेती प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों में होती है।

बुआई और सिंचाई

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी बुआई 30 नवंबर तक हो जानी चाहिए। यदि बुआई पंक्तियों में की जा रही है तो प्रति एकड़ भूमि में 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। बुवाई करने के बाद अच्छी फसल के लिए 4 से 5 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के 3 सप्ताह बाद करें। इसके बाद कलियां फूटते समय, बालियां निकलने से पहले, बालियों में दूध आते समय तथा दानों के पकने के समय सिंचाई करनी चाहिए।

कब करें कटाई

विशेषज्ञों के अनुसार जब काले गेहूं के पौधों में लगे दाने पककर कठोर हो जाएं और दानों में 20-25 प्रतिशत नमी बची रहे तो इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। एक बीघा खेत से 10 से 12 क्विंटल गेहूं का उत्पादन मिल जाता है।

किसानों के लिए फायदेमंद मिर्च की उन्नत खेती

भोपाल। मिर्च की खेती की गणन नगदी खेती के रूप में की जाती है। इसे किसी भी जलवायु में लगाया जा सकता है। मिर्च की उन्नत खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई मिट्टी चाहिए, जिसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लवण और क्षार युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। खेत को तीन-चार बार जुताई कर तैयार करना चाहिए। 1.25 से 1.50 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर खेती की आवश्यकता होती है।

खाद एवं बीज उपचार

प्रति क्यारी 50 ग्राम फोरेट और सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। बीज को 2 ग्राम एग्रोसन जीएन, थीरम या कैप्टान रसायन प्रति किग्रा उपचारित करें। बीज को पंक्ति यों में एक इंच की दूरी पर बोकर मिट्टी और खाद से ढक दें। ऊपर पुआल या खरपतवार से ढक देना चाहिए। बीज जमने के बाद खरपतवार को बाहर निकालें। पौधे 25 से 35 दिन में बोया जा सकता है। रात को रोपाई करें। रोपाई करते समय कतार और पौधों में 45 सेमी की दूरी होनी चाहिए। 85 से 95 दिन में हरी मिर्च फल देने योग्य हो जाती है। सूखी मिर्च के फल को 140-150 दिन में रंग लाल होने पर तोड़ना चाहिए। 200 कुंतल गोबर या कंपोस्ट, 100 कुंतल नाइट्रोजन, 50 कुंतल फास्फोरस और 60 कुंतल पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। रोपाई से पहले, कंपोस्ट में फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा दी जानी चाहिए, फिर, दो बार में, शेष मात्रा दी जानी चाहिए। यदि कम बारिश हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल फूल और फल बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई नहीं होने पर फल और फूल छोटे हो जाते हैं। खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि अच्छी फसल हो सके।

जलवायु और मिट्टी आलू के उत्पादन के लिए अनुकूल

आलू उत्पादन में यूपी अव्वल एमपी को छठवें पायदान पर

भोपाल। जागत गांव हमार

आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है और आलू रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका उपयोग हर घर में किया जाता है। भारत में चावल, गेहूं और गन्ने के बाद आलू की खेती सबसे अधिक की जाती है। आलू में 80 से 82 प्रतिशत तक पानी और 14 प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे कितने भी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। वहीं आलू के कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। शायद इसलिए इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। दरअसल आलू के पराठे से लेकर चिप्स और कई तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। जो हर किसी को पसंद आती है। भारत में आलू उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अव्वल राज्य है। यहां की जलवायु और मिट्टी आलू के उत्पादन के लिए अनुकूल है। इस वजह से सबसे अधिक आलू का उत्पादन यूपी में होता है। आंकड़ों के अनुसार देश में कुल उत्पादित होने वाले आलू में से उत्तर प्रदेश में अकेले 29.65 प्रतिशत आलू का उत्पादन किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आलू उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में छठे नंबर आ गया है।

आलू में पाए जाने वाले पोषक तत्व-

आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. आलू में फाइबर जिंक आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इतना ही नहीं इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, बी-कॉम्प्लेक्स, विटामिन-सी की भी भरपूर मात्रा होती है जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं।

ग्वालियार में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हमारे यहां के आलू का सबसे बड़ा खरीदार है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्वालियर की मिट्टी गुणवत्ता वाले आलू के उत्पादन के लिए सबसे मुफीद है। इसीलिए यहां केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। यूपी के किसान अनुसंधान केंद्र में पैदा किए जा रहे गुणवत्ता और स्वाद से पूर्ण आलू के बीज से बंपर उत्पादन लेकर शुगर फ्री आलू के रूप में ब्रांडिंग कर बेच रहे हैं।

मप्र के छह जिले आलू उत्पादन में आगे

मध्य प्रदेश के 6 जिले आलू उत्पादन में अव्वल हैं। आलू प्रसंस्करण के क्षेत्र में एमपी देश के आदर्श राज्यों के रूप में उभर रहा है। आलू उत्पादन में प्रदेश का छठा स्थान दर्ज किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका मालवा क्षेत्र की बताई जा रही है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भोपाल में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन होता है। इसके अलावा वर्तमान समय में छिंदवाड़ा, सीधी, सतना, रीवा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, विदिशा, रतलाम और बैतूल में भी किसानों का आलू उत्पादन की ओर आकर्षण बढ़ा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश देश के आलू उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले प्रदेशों में ऊपर के स्थान पर आ गया है।

किसानों की ओर से दिखाई जा रही है रुचि

मालवांचल ही नहीं, बल्कि एमपी के आलू की काफी डिमांड होती है। एमपी में आलू के भाव भी हमेशा बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त चिप्स की फैक्ट्रियों की ओर से भी लगातार आलू की डिमांड बढ़ रही है। इसी वजह से एमपी के किसान आलू उत्पादन के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। आलू के दाम अधिक होने से कई किसानों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई है। इसी वजह से आलू की खेती में किसान लगातार रुचि दिखा रहे हैं।

मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसान भी अलग-अलग प्रकार की खेती कर लाभ कमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज को लेकर सब्सिडी दी है। जिसकी वजह से किसानों को आलू रखना काफी आसान हो गया है। यह भी एक वजह है कि अधिक किसानों की ओर से लगातार आलू की खेती की जा रही है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री, मप्र

अल नीनो के कारण टूटेगा 15 साल का रिकॉर्ड

चिंता! प्रदेश के कपास की उत्पादन में आएगी गिरावट

भोपाल। जागत गांव हमार

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने अपने पहले फसल अनुमान में कहा है कि 2023-24 में कॉटन उत्पादन 295.10 लाख गांठ होगा। जो पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। 2023-24 के लिए अनुमान पिछले वर्ष के 318.90 लाख गांठ से 7.5 प्रतिशत कम है। सीएआई के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा कि 2008-09 के बाद, यह सबसे कम कपास उत्पादन है। उन्होंने उत्पादन में गिरावट के लिए मौजूदा अल नीनो के प्रभाव और कपास क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत की कमी को जिम्मेदार ठहराया। सीएआई को उम्मीद है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण विभिन्न उत्पादक राज्यों में पैदावार में 5-20 प्रतिशत की कमी आएगी।

एसोसिएशन ने हालिया बैठक में फसल अनुमानों को अंतिम रूप दिया। साथ ही अगली बैठक में स्थिति का जायजा लेने की उम्मीद जताई। पिछले सप्ताह जारी अपने पहले अग्रिम अनुमान में, कृषि मंत्रालय ने 2023-24 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 170 किलोग्राम की 316.6 लाख गांठों का लगाया था, जबकि पिछले वर्ष का अंतिम अनुमान 336.6 लाख गांठ था। सीएआई ने 2023-24 सीजन के दौरान अधिशेष 35 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है, जबकि 14 लाख गांठ (पिछले साल 15.50 लाख गांठ) निर्यात का अनुमान लगाया है। कॉटन बैलेंस शीट के अनुसार, सीएआई को 2023-24 सीजन के लिए अंतिम स्टॉक 21 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 28.9 लाख गांठ से कम है।

घरेलू मांग 311 लाख गांठ होने का अनुमान

सीएआई को पिछले वर्ष के 12.50 लाख गांठ की तुलना में 22 लाख गांठ कपास का अधिक आयात होने का अनुमान है। क्योंकि वर्तमान कॉटन उत्पादन कम होकर 295.10 लाख गांठ रह गया है। इसलिए आयात बढ़ेगा। शुरुआती स्टॉक 28.90 लाख गांठ है। 2023-24 सीजन के दौरान कपास की कुल उपलब्धता 346 लाख गांठ आंकी गई है, जो पिछले साल के 355.40 लाख गांठ से कम है। सीएआई द्वारा 2023-24 सीजन के दौरान कुल घरेलू मांग 311 लाख गांठ होने का अनुमान है। इसमें मिलों की खपत 280 लाख गांठ और लघु उद्योग (एसएसआई) की खपत 15 लाख गांठ शामिल है।

किस क्षेत्र में कितना कम हुआ उत्पादन

सीएआई ने उत्तरी क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 43 लाख गांठ फसल का अनुमान लगाया है। इसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। मध्य क्षेत्र में, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसमें सीएआई द्वारा अनुमानित उत्पादन 179.60 लाख गांठ बताया गया है, जो पिछले साल के 194.62 लाख गांठ से कम है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले दक्षिण क्षेत्र में उत्पादन पिछले साल के 74.85 लाख गांठ से कम होकर 67.50 लाख गांठ रह गया है।

-मोटे अनाज की कुकीज, बिस्कुट लोग कर रहे पसंद

अब बाजार में मिलेट्स की मिठाइयां और चाकलेट्स का मिलेगा स्वाद

भोपाल। जागत गांव हमार

लोगों का इस दीपावली स्वाद कुछ अलग ही होगा। क्योंकि, इस बार परंपरागत मिठाइयों और चाकलेट्स के अलावा मिलेट्स यानी मोटे अनाज की मिठाइयां, कुकीज और बिस्कुट बाजार में आ गए हैं। बाजरे की मिठाइयां और कार्न के लड्डू लोगों को खूब भा रहे हैं। कई बड़ी फूड कंपनियों के आउटलेट्स पर मिलेट्स के स्पेशल फूड भी बिक रहे हैं। दुकानदार त्योहारी सीजन में रागी, फॉक्सटेल बाजरा और अन्य प्रकार के मोटे अनाजों का उपयोग पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन के बनाने में कर रहे हैं। बाजरा-आधारित नमकीन के साथ ही इस बार दीपावली में गेहूं का हलवा, पंधारी लड्डू, कंबु कारा सेव और रागी पकौड़ा जैसे पारंपरिक पसंदीदा व्यंजनों की डिमांड बढ़ी है।

मिठाइयों के साथ सेहत की बात

विक्रेताओं का कहना है कि अब धारणा बदल रही है। नयापन नहीं होगा तो बिक्री भी नहीं होगी। साथ ही लोगों की यह धारणा भी बदलनी है कि स्वास्थ्य स्वादिष्ट नहीं है। या फिर सेहत बनाए रखना है तो स्वाद से समझौता करना होगा। यानी मिठाइयों से परहेज करना होगा। लोग अब सेहत के साथ स्वाद भी यादगार रखना चाहते हैं।

मधुमेह रोगियों का ख्याल

मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए परंपरागत मिठाइयों से हटकर इस बसा रागी,मक्का। और ज्वार-बाजरे की रेसिपी और इनसे बनी मिठाइयां बाजार में हैं। इन मिठाइयों में मैदा, पनीर की जगह मूंगफली और तिल जैसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। लोग सफेद चीनी के इस्तेमाल से बच रहे हैं। इसलिए गुड़, पाम गुड़, या ब्राउन शुगर का उपयोग हो रहा है। बादाम, केसर पाक, काजू बर्फी, सोन पापड़ी आदि में भी रागी व फ्लैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजरा, नट्स और बीजों का उपयोग करके शाकाहारी प्रोटीन युक्त मिठाइयां बन रही हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)